एकाधिकार गृहों की ओर बकाया धनराशि

2482. **श्री शिव चरण वर्मा :**

श्री त्रिलोक चन्द :

क्या श्रम मंत्री, मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1580 के उत्तर तथा 10 अप्रैल, 1981 को एकाधिकार गृहों की ओर बकाया के बारे में आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए सभा पटल पर रखे विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके पते अभी तक ढूंढे नहीं जा सके हैं और ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन पर श्रम कानून लागू नहीं होते तथा ऐसे कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अभी तक बकाया की अदायगी नहीं की है ; और

(ख) क्या उन सभी कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 1580 तारीख पहली मार्च, 1979 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने में सदन की मेज पर रखे गए विवरण में दी गई सूचना के अतिरिक्त कोई और सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों / विभागों और कार्यालयों तथा राज्य सरकारों से इस मामले में समुचित कार्यवाही करने के लिए कहा जा रहा है ।

News Item "Resurgence of Left Extremist" Activity

2483. SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to a news item under caption "Government alerts States-Resurgence of left extremist activity" appearing in Sunday English Daily "Pioneer" Lucknow city edition dated 26th July, 1981;

(b) the reaction of Government in this respect and the steps taken to check this menace;

(c) the number of cases of violence during the last three years and the current year separately because of this menace (state-wise and year-wise); and

(d) the action taken by the Government to meet this situation arising out of the increasing cases of violence ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). The Government have seen the Press Report referred to. Law and order primarily concerns the State Governments. The Central Government keeps in touch with the State Governments and offers such guidance and assistance as may be necessary from time to time.

(c) and (d). The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.